Hindustan, Aurangabad, 08/10/2026
Page No: 2, Size: 19.05cm × 42.33cm

सुनवाई:जेलों में कैदियों का इलाज और स्कूलों में खाने की गुणवत्ता जरूरी



दो दिवसीय खुली सुनवाई के पहले दिन बुधवार को पटना के ज्ञान भवन में मामलों की सुनवाई करते राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस वी. रामा सुब्रमण्यम और सदस्य डॉ. जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी एवं विजया भारती सयानी की पूर्ण पीठ।

पटना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा कि जेलों में कैदियों के इलाज की व्यवस्था और स्कूल-आश्रय घारों में खाने की गुणवत्ता आवश्यक है। आयोग ने राज्य सरकार को सचेत रहने और इसकी पुनरावृत्ति से बचने के लिए जरूरी कदम उठाने का आदेश दिया है।

आयोग ने अधिकारियों से इसकी विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। बुधवार को ज्ञान भवन में आयोग के अध्यक्ष जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम एवं दो सदस्यों डॉ जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी और विजया भारती सयानी ने विभिन्न जिलों से संबंधित मामलों की सुनवाई की।

आयोग ने 11 नवंबर, 2024 को पटना के पटेल नगर स्थित आश्रय घर में फूड प्वाइजनिंग से तीन लड़कियों की मौत और 13 के बीमार पड़ने के मामले की सुनवाई की।

खत्म कर दीजिए हुजूर, यह सब अफवाह है : आयोग ने 24 अप्रैल, 2025 को मोकामा के एक स्कूल में मिड डे मील खाने पर छात्राओं के बीमार पड़ने से संबंधित मामले में स्थानीय लोगों के आग्रह पर केस बंद कर दिया। खाने में छिपकली गिरने की शिकायत थी। पटना जिला के संबंधित पदाधिकारी के साथ पहुंचे ग्रामीणों ने कहा कि बच्चों को अस्पताल जाने पर 20-20 हजार रुपये का लालच दिया गया।

वहां पर हिंग पिला देने से कुछ बच्चियों को उल्टी हो गयी। इसको फूड प्वाइजनिंग के रूप में प्रचारित किया गया। केस खत्म कर दीजिए हुजूर, यह सब अफवाह है।

नर्सिंग होम पर जानकारी मांगी

आयोग ने मुंगेर में कई अस्पताल व नर्सिंग होम के बिना रजिस्ट्रेशन चलने से संबंधित छपी खबर मामले में सुनवाई की। आयोग ने अधिकारियों से पूछा कि 40 बेड से कम और उससे अधिक बेड वाले अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन को लेकर क्या नियम हैं, इसकी जानकारी चार हफ्ते में दें।

Hindustan, Patna, 08/10/2026
Page No: 1, Size: 20.66cm × 43.10cm

नाबालिग से दुष्कर्म, हिरासत में मौत पर मुआवजे का आदेश

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की पूर्ण पीठ ने मनेर में नाबालिग से रेप व हत्या और पटना के बेऊर जेल में दो कैदियों की मौत मामले में राज्य सरकार को मुआवजा देने का आदेश दिया है।

आयोग ने कहा कि नाबालिग पीड़िता के परिवार को पांच लाख रुपये जबकि बेऊर जेल में बंद दो विचाराधीन कैदियों (23 साल के सचिन कुमार और 55 साल के राजवीर) की मौत पर उनके परिजनों को क्रमशः तीन लाख व पांच लाख रुपये मुआवजा का भुगतान चार हफ्ते के भीतर सुनिश्चित किया जाए। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम और सदस्य डॉ जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी एवं विजया भारती सयानी की पूर्ण पीठ ने दो दिवसीय कैंप सिटिंग के पहले दिन पटना के ज्ञान भवन में 30 मामलों की सुनवाई की। इनमें सर्वाधिक आठ मामले पटना और आठ राज्य के विभिन्न जेलों से संबंधित रहे।

मुंगेर जिले में बिना रजिस्ट्रेशन कई हॉस्पिटल व नर्सिंग होम चलने से संबंधित मामले में राज्य सरकार से चार हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट तलब की गयी। सारण के संतोष कुमार साह से संबंधित मामले में 12 आरोपियों में से आठ का नाम चार्जशीट में नहीं रखने की शिकायत पर आयोग ने जांच का आदेश दिया है। मुजफ्फरपुर की अनिता देवी की प्रताड़ना का मामला बंद कर दिया गया, क्योंकि पुलिस के मुताबिक चार अभियुक्तों पर चार्जशीट दाखिल हो गयी है। सुनवाई शुक्रवार को भी जारी रहेगी।

30 मामलों की सुनवाई पहले दिन मानवाधिकार आयोग की पूर्णपीठ ने

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पीठ पटना में आज भी खुली सुनवाई करेगी
- बेऊर जेल में 23 साल और 55 साल के दो कैदियों की मौत पर मिलेगा मुआवजा

मनेर पीड़िता की बुआ ने बताया दर्द: सुनवाई में 26 अगस्त 2025 को रेप कर हत्या की शिकार मनेर (पटना) की 10 वर्षीय नाबालिग की बुआ पहुंची थी। उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी भोला राय जेल में है, मगर चार अन्य आरोपी फरार हैं। पीड़िता की मां की मृत्यु हो चुकी है, जबकि पिता गैर जिम्मेदार हैं। दो छोटे भाई-बहनों की जिम्मेदारी भी उन पर है। आयोग ने पांच लाख मुआवजे का आदेश दिया। देखें P 04

Prabhat Khabar, Patna, 08/10/2026
Page No: 4, Size: 12.04cm × 11.09cm

मनेर में नाबालिग से दुष्कर्म-हत्या व बेऊर जेल में कैदी की मौत के मामलों में पांच-पांच लाख मुआवजा का आदेश

पटना . राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की ओर से ज्ञान भवन में आयोजित दो दिवसीय खुली सुनवाई के पहले दिन बुधवार को कुल 30 मामलों की सुनवाई की गयी. आयोग के अध्यक्ष जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम, सदस्य डॉ जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी और सदस्य विजया भारती सयानी ने सुनवाई के दौरान आयोग ने कई मामलों में पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा देने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान मनेर में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पीड़ित परिवार को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया गया. आयोग ने संबंधित अधिकारियों को मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया.वहीं, बेऊर जेल में 23 वर्षीय कैदी सचिन कुमार की मौत के मामले में आयोग ने मृतक के परिजनों को तीन लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया. इसी तरह बेऊर जेल में 55 वर्षीय कैदी राजवीर की मौत के मामले में उसके परिजनों को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया गया.

प्रभात खबर
Thursday, October 8, 2026
Patna-City
https://epaper.prabhatkhabar.com/clip/6ac6a0efa2f3bdc19befa14c

Dainik Jagran, Meerut, 08/10/2026
Page No: 2, Size: 4.82cm × 5.69cm

मानवाधिकार आयोग ने रसिक दुलारी की मौत में लिया संज्ञान

मथुरा : संत प्रेमानंद के शिष्य रसिक दुलारी शरण उर्फ दीपक लोधी की 25 सितंबर को वृंदावन स्थित गुरु कृपा कुंज में आत्महत्या के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने प्रकरण में आवश्यक जांच और कार्रवाई के लिए अपर पुलिस महानिदेशक आगरा को निर्देश दिए हैं। -जासं

Dainik Bhaskar, Patna, 08/10/2026
Page No: 2, Size: 26.30cm × 11.06cm

भास्कर खास ज्ञान भवन में एनएचआरसी की महासुनवाई: 30 में से 25 मामलों का मौके पर निपटारा

सेप्टिक टैंक में मौतों पर 30-30 लाख मुआवजा, 25 केस बंद

भास्कर न्यूज | पटना

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की ज्ञान भवन में हुई सुनवाई के पहले दिन ऐतिहासिक फैसले आए। आयोग अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यम, सदस्य न्यायमूर्ति डॉ. विद्युत रंजन सारंगी व विजया भारती सयानी की पीठ ने सीतामढ़ी में 2022 में सेप्टिक टैंक सफाई में मृत दो मजदूरों के परिजनों को 30-30 लाख (कुल 60 लाख) मुआवजा देने का आदेश दिया। इसकी शिकायत आमिर सुबहानी ने की थी। आयोग ने सरकार को कुल करीब 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया। 5 घंटे चली सुनवाई में 17 जिलों के 30 मामले आए, जिनमें 25 केस ऑन-द-स्पॉट बंद कर दिए गए। गुरुवार को 40 केस सुने जाएंगे। एडीजी मुख्यालय केएस अनुपम, गृह विशेष सचिव छत्रनील सिंह, जेल आईजी रजनीश कुमार सिंह व डीआईजी लीगल सुशील कुमार मौजूद थे। 30 मामलों में सर्वाधिक 6 जेल हिरासत में मौत, 6 महिला प्रताड़ना, 2 बाल सुधार गृह में मौत व 11 स्वतः संज्ञान के केस थे। जिलों में पटना के 8, मुजफ्फरपुर के 5, पूर्वी चंपारण-दरभंगा के 2-2 मामले थे।

मामले और निर्देश: ज्ञान भवन में ऑन-द-स्पॉट फैसले

सेप्टिक टैंक में मौत (सीतामढ़ी, 2022) आमिर सुबहानी की शिकायत।
निर्देश: दोनों मृतकों के आश्रितों को 30-30 लाख रु. मुआवजे का आदेश।
रेप-चिटफंड पीड़िता को धमकी (मुजफ्फरपुर) अहियापुर थाने के केस में धमकी की शिकायत।
निर्देश: एडीजी केएस अनुपम को 2 हफ्ते में महिला आईपीएस के नेतृत्व में एसआईटी बनाने व नंबर देने का आदेश।
बेऊर जेल में मौत (पटना) राजवीर सिंह (55 वर्ष) व सचिन कुमार (23 वर्ष, तिसखोर) की मौत का मामला।
निर्देश: राजवीर के परिजनों को 5 लाख व सचिन को 3 लाख मुआवजा और इलाज के निर्देश।



11 साल की बच्ची से गैंगरेप-हत्या (मनेर): आरोपी भोला राय मामले में अनाथ बच्ची की फुआ, दादी व भाई पहुंचे।
निर्देश: फुआ के खाते में 5 लाख एफडी कराने व मुजफ्फरपुर की दिव्यांग महिला की शिकायत पर संज्ञान।
मिड-डे मील में लापरवाही (नालंदा, पटना, मोकामा): बच्चे बीमार पड़ने व मेकरा में सांप की अफवाह।
निर्देश: मेकरा केस बंद कर स्वच्छता व भोजन जांच के निर्देश।

भास्कर एनालिसिस

तंत्र की नाकामी पर आयोग का चाबुक

1. **प्रशासनिक लापरवाही:** सेप्टिक टैंक में मौतें व मिड-डे मील में बच्चे बीमार पड़ना जिला प्रशासन की घोर लापरवाही है।
2. **जेल प्रबंधन की विफलता:** इलाज के अभाव में हिरासत में मौत जेल प्रशासन की नाकामी है, जहां अफसरों पर कार्रवाई जरूरी है।
3. **त्वरित न्याय का संदेश:** एक दिन में 25 केस निपटाकर आयोग ने साफ किया कि मानवाधिकार हनन बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसा होने पर कार्रवाई भी की जाएगी।

Dainik Bhaskar, Bhagalpur, 08/10/2026
Page No: 4, Size: 7.96cm × 9.34cm

बंधुआ मजदूरी के आरोपों की जांच के लिए टीम गठित

मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर एसपी ने आदेश दिए

करैला गांव निवासी सदानंद यादव एवं अन्य ने शिकायत दर्ज कराई थी

क्राइम रिपोर्टर | भागलपुर

जिले में बंधुआ मजदूरी से जुड़े मामले की जांच के लिए जांच दल का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के निर्देश के आलोक में एसएसपी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।

इसके तहत जांच टीम में मोजाहिदपुर के सर्किल इंस्पेक्टर गोपाल कुमार को शामिल होने के लिए कहा गया है। मधुसूदनपुर के करैला गांव निवासी सदानंद यादव एवं अन्य ने बंधुआ मजदूरी से संबंधित शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दर्ज कराई थी। आयोग की ओर से निर्देश मिलने के बाद जांच की प्रक्रिया शुरू की गई है। वादी सदानंद यादव ने बताया कि वह एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी में काम करते थे। एजेंसी की तरफ से कोई सुविधा नहीं दी जाती थी। इसकी शिकायत करने पर हमलोगों को काम से निकाल दिया गया। इसी मामले में हमलोगों ने मानवाधिकार आयोग में दो वर्ष पहले शिकायत की थी।

Source: https://www.latestly.com/agency-news/world-news-indias-south-south-cooperation-highlighted-at-un-human-rights-council-7636321.html

World News | India's South-South Cooperation Highlighted at UN Human Rights Council

Get latest articles and stories on World at LatestLY. Hansraj Singh of Sambhali Trust addressed the Council, focusing on the importance of practical knowledge-sharing, institutional cooperation and capacity-building in strengthening human rights institutions.

By ANI | Published: Oct 07, 2026 08:22 PM IST

Geneva [Switzerland], October 7 (ANI): India's experience in South-South cooperation and human rights capacity-building was highlighted during a General Debate at the 63rd Session of the United Nations Human Rights Council in Geneva.

Hansraj Singh of Sambhali Trust addressed the Council, focusing on the importance of practical knowledge-sharing, institutional cooperation and capacity-building in strengthening human rights institutions.

Highlighting India's experience through the International Cooperation and Training Programme (ITEC), Singh referred to a six-day programme held in September 2025. Organised by the National Human Rights Commission of India in collaboration with the Ministry of External Affairs, the programme brought together 43 senior officials from 12 national human rights institutions for training on governance and human rights.

Singh presented the Indian experience as an example of how South-South cooperation can strengthen institutions through the exchange of practical knowledge and the development of institutional capacities. He stressed that technical assistance is most effective when it responds to actual needs, reflects local realities and enables institutions to continue their work independently after external support ends.

Drawing on Sambhali Trust's grassroots experience in Rajasthan, Singh further emphasised that capacity-building must ultimately reach communities at the last mile. He said training and technical assistance become more meaningful when accompanied by information in simple language, locally relevant examples and follow-up support, helping communities and civil society organisations understand and apply the knowledge gained.

Singh also encouraged the United Nations and Member States to strengthen such approaches by involving national institutions, local bodies and grassroots organisations wherever appropriate. He further stressed that the effectiveness of capacity-building programmes should be measured not simply by the number of participants trained, but by their practical and lasting impact.

The intervention concluded with a message on the importance of sustainable knowledge transfer. "Capacity-building succeeds when knowledge remains after the experts have left," Singh said.

Through the intervention, Sambhali Trust highlighted India's role in promoting practical and knowledge-based

South-South cooperation in the human rights sector, while underlining the importance of linking institutions, civil society and grassroots communities for sustainable capacity-building. (ANI)

Source: https://www.tribuneindia.com/news/world/indias-south-south-cooperation-highlighted-at-un-human-rights-council/amp

Home / World / Indias South South Cooperation Highlighted At Un Human Rights Council

India's South-South Cooperation highlighted at UN Human Rights Council

ANI
Updated At : 07:01 PM Oct 07, 2026 IST

Geneva [Switzerland], October 7 (ANI): India's experience in South-South cooperation and human rights capacity-building was highlighted during a General Debate at the 63rd Session of the United Nations Human Rights Council in Geneva.

Hansraj Singh of Sambhali Trust addressed the Council, focusing on the importance of practical knowledge-sharing, institutional cooperation and capacity-building in strengthening human rights institutions.

Highlighting India's experience through the International Cooperation and Training Programme (ITEC), Singh referred to a six-day programme held in September 2025. Organised by the National Human Rights Commission of India in collaboration with the Ministry of External Affairs, the programme brought together 43 senior officials from 12 national human rights institutions for training on governance and human rights.

Singh presented the Indian experience as an example of how South-South cooperation can strengthen institutions through the exchange of practical knowledge and the development of institutional capacities. He stressed that technical assistance is most effective when it responds to actual needs, reflects local realities and enables institutions to continue their work independently after external support ends.

Drawing on Sambhali Trust's grassroots experience in Rajasthan, Singh further emphasised that capacity-building must ultimately reach communities at the last mile. He said training and technical assistance become more meaningful when accompanied by information in simple language, locally relevant examples and follow-up support, helping communities and civil society organisations understand and apply the knowledge gained.

Singh also encouraged the United Nations and Member States to strengthen such approaches by involving national institutions, local bodies and grassroots organisations wherever appropriate. He further stressed that the effectiveness of capacity-building programmes should be measured not simply by the number of participants trained, but by their practical and lasting impact.

The intervention concluded with a message on the importance of sustainable knowledge transfer. "Capacity-building succeeds when knowledge remains after the experts have left," Singh said.

Through the intervention, Sambhali Trust highlighted India's role in promoting practical and knowledge-based South-South cooperation in the human rights sector, while underlining the importance of linking institutions, civil society and grassroots communities for sustainable capacity-building. (ANI)

Brut, Online News, 08/10/2026

Source: https://www.brut.media/in/videos/india/society/nagaland-women-allege-kidnapping-attempt-outside-five-star-hotel-in-delhi-s-chanakyapuri

Nagaland Women Allege Kidnapping Attempt Outside Five-Star Hotel In Delhi's Chanakyapuri

Nagaland women allege three men tried to force them into a car outside a five-star hotel in Delhi's Chanakyapuri. They also alleged FIR delay.

Published on 07/10/2026

Three women from Nagaland have alleged that three unidentified men tried to grab them and force them into a car outside a five-star hotel in Chanakyapuri, Delhi. According to the women, the incident took place near the exit gate in the hotel's parking area. They alleged that the men had removed the car's number plate. One of the women said that when their male friends intervened, the men attacked one of them with a hockey stick and an iron rod. The injured man was later taken to RML Hospital and, according to the woman, remains admitted.

The women said they called the police after the incident. They alleged that they were taken to a police station and made to wait for hours. One woman alleged that the police did not initially register an FIR or record their complaint. The women were later taken to hospital, where medical examinations were conducted, according to their statements. The victims said the police have seized the car and their phones, which they believe could contain evidence related to the incident.

One of the women said she is from Nagaland and has been living in Delhi for several years. She alleged that the incident involved an attempt to kidnap them and said she wanted the men to be arrested.

According to the National Human Rights Commission, nearly 24,500 people were reported missing in Delhi in 2025. Around 60% were women, while nearly 37% of the cases remained unresolved. The NHRC has also stated that since 2016, nearly 3,500 teenage girls have gone missing in Delhi every year.

Source: https://odishabytes.com/nhrc-probes-into-assault-of-woman-sarpanch-chameli-ojha-in-odisha/

NHRC Probes Into 'Assault' Of Woman Sarpanch Chameli Ojha In Odisha
by OB Bureau October 7, 2026 in Kendrapada, News, Odisha Reading Time: 2 mins read

Kendrapada: A three-member team of National Human Rights Commission (NHRC) team has started a ground investigation into the alleged assault of a woman sarpanch by police and a BDO in Kendrapada district. Earlier this year, Tikhiri gram panchayat sarpanch Chameli Ojha had alleged that she was assaulted by police after questioning officials over pending payments for development works and alleged irregularities in the panchayat.

The NHRC team, comprising Deputy Superintendent of Police Isam Singh, Gugan Ram and Shashi Bala Sharma, arrived in Kendrapada on Monday night to investigate Ojha's complaint. The inquiry began on Tuesday at Mahakalapada police station, where the team recorded the statements of then IIC Manas Kumar Mallick and other police personnel. Thje team later questioned Mahakalapada BDO Rabi Narayan Acharya and other block officials. The NHRC team subsequently visited Ojha at her residence in Tikhiri and recorded her statement and those of local villagers.

Ojha has alleged that she was abused and assaulted by police after being taken from the BDO's office on 11 June. She claimed the incident followed her demand for clearance of pending bills for development works in her panchayat and allegations that officials were obstructing the projects.

During its four-day inquiry, the NHRC team is expected to record statements of eyewitnesses, doctors at the Kendrapada district headquarters hospital and others connected with the case. It will also examine official records and available video footage and scrutinise the police and administrative versions of the incident, officials said.

It was also alleged that Ojha was implicated in a criminal case registered on the BDO's complaint, and booked under charges including attempt to murder, causing hurt and obstructing a public servant. The NHRC subsequently sought a report from the Kendrapada district magistrate and superintendent of police. The SP reported that three FIRs had been registered in connection with the incident and described them as cross-cases. Ojha had earlier approached Chief Minister Mohan Charan Majhi, alleging that officials were withholding payments for completed development works.

Source: https://rawlaw.in/students-allege-police-excesses-inside-jamia-during-anti-caa-protests-delhi-high-court-refuses-fresh-sit-compensation-and-new-campus-policing-guidelines-six-years-later/

Students Allege Police Excesses Inside Jamia During Anti-CAA Protests; Delhi High Court Refuses Fresh SIT, Compensation and New Campus Policing Guidelines Six Years Later

Rawlaw October 7, 2026

Jamia Protesters Seek Independent Probe and Compensation for December 2019 Police Action; Delhi High Court Says NHRC Inquiry, Crime Branch Investigation and Existing Remedies Make Fresh Writ Intervention Unwarranted

Facts

The batch of eight writ petitions arose from events at and around Jamia Millia Islamia University in December 2019, in the backdrop of protests against the Citizenship Amendment Act, 2019 and the proposed NRC. The petitioners alleged that police and paramilitary personnel used excessive force, entered the University campus without authorization, deployed tear gas in enclosed academic spaces including the library, assaulted students and staff, detained students, and interfered with access to legal assistance. The State maintained that the protests had escalated into violence, arson, damage to public and private property and attacks on police personnel, requiring intervention to restore public order.

During the pendency of the petitions, several original prayers became infructuous. The petitioners ultimately confined their case to four broad surviving areas: an independent judicial commission/SIT or other neutral inquiry into alleged police excesses; compensation and reimbursement of medical expenses; fresh safeguards regulating police action during protests in educational institutions; and preservation of CCTV footage and other evidence.

Two criminal cases, FIR Nos. 242/2019 and 298/2019, had been registered and transferred to a Special Investigation Team of the Crime Branch, which filed charge-sheets. Separately, the NHRC investigated complaints concerning the events of 15 December 2019. Its report dated 18 May 2020 found that the protests had at places turned violent and necessitated police intervention, while also recording lack of restraint in certain police/RAF actions, including use of force against students and tear gas in the library. The NHRC recommended compensation for injured students, accountability measures, police training and institutional reforms. Jamia Millia Islamia also pursued an application under Section 156(3) CrPC against police officials; it was dismissed on 3 February 2021, primarily for want of sanction under Section 197 CrPC, and that order was not challenged.

Issues

Whether the circumstances justified constitution of an independent judicial commission, court-monitored committee, SIT, fact-finding body or transfer/fresh investigation into alleged police excesses and criminal acts by public officials.

Whether compensation, reimbursement of medical expenses or other public-law monetary relief should be awarded under Article 226 for injuries and alleged rights violations.

Whether the Court should frame fresh guidelines specifically regulating police entry, use of force and intervention during protests within educational institutions.

Whether further directions were necessary for preservation of CCTV footage, electronic records and other evidence relating to the December 2019 incidents.

Petitioners' Arguments

The petitioners contended that once the crowd had retreated into the University, there was no justification for police to pursue students into the campus, library and academic facilities. They relied on the Chief Proctor's statement that permission had not been obtained before police entry, and argued that statutory safeguards governing dispersal of assemblies and use of force were not followed. Ramlila Maidan Incident and Anita Thakur were invoked to emphasize necessity, proportionality and restraint. They stressed that the NHRC itself had found certain police action inside the library avoidable and lacking restraint. Since the allegations were substantially against police personnel, they argued that allowing the police machinery to examine its own conduct offended the principle that no person should be a judge in his own cause, warranting an independent inquiry or SIT.

On compensation, the petitioners relied on injuries allegedly suffered by students, including serious and permanent injuries, and submitted that private financial assistance could not substitute public-law compensation for violation of fundamental rights. Rudul Sah, Bhim Singh and Nilabati Behera were relied upon. They also sought specific policing safeguards for educational campuses and continued preservation of electronic evidence.

Respondents' Arguments

The State raised a preliminary objection that most petitions were in the nature of PILs concerning criminal investigation even though the petitioners were not direct victims. It argued that the criminal-law machinery had already been activated: FIRs were registered, the Crime Branch SIT investigated, charge-sheets were filed and proceedings were pending before competent courts. The State further relied on the completed NHRC inquiry, which had not been challenged, and the finality of the dismissal of Jamia's Section 156(3) CrPC application. It submitted that no material demonstrated that the investigation was tainted, biased or incapable of inspiring confidence.

On compensation, it argued that the NHRC had already recommended remedial measures and the petitioners had not pursued those avenues. It also maintained that existing constitutional, statutory and judicial safeguards sufficiently regulate police action and that CCTV/electronic material had already been preserved.

Analysis of the Law

The Court emphasized that Article 226 undoubtedly empowers a High Court to direct an independent investigation, but such power is extraordinary and must be exercised sparingly. A transfer or fresh independent investigation is ordinarily justified only in rare and exceptional cases where credibility, fairness, public confidence or enforcement of fundamental rights demonstrably requires it. Once investigation has substantially progressed and charge-sheets have been filed, superior courts ordinarily should not reopen the investigative process without compelling material.

The Court also reiterated that criminal law contains its own remedial hierarchy. Complaints about non-registration or deficient investigation ordinarily have remedies before superior police officers and the Magistrate. Although the Article 226 remedy is not mutually exclusive, the same grievance should not ordinarily be reopened constitutionally after the statutory route has been invoked and adjudicated, absent exceptional circumstances.

Public-law compensation remains available for an established infringement of fundamental rights, but the Court distinguished cases where such violation was proved or undisputed. Where the facts remain contested, a statutory human-rights body has already examined the matter and recommended remedies, and individual claimants retain ordinary remedies, Article 226 need not be used to bypass those mechanisms.

As to policing standards, the Court held that necessity, reasonableness, restraint and proportionality already govern State coercive action under the Constitution, statutes, police manuals and binding Supreme Court precedent. An alleged violation of an existing safeguard does not itself prove that the safeguard is inadequate or require creation of a new campus-specific legal regime.

Precedent Analysis

State of West Bengal v. Committee for Protection of Democratic Rights and K.V. Rajendran were applied for the proposition that constitutional courts may transfer an investigation, but only sparingly and in rare or exceptional situations. Romila Thapar reinforced that parties cannot demand an investigating agency of their choice merely by alleging bias. Sakiri Vasu was relied upon to stress statutory remedies under Sections 154(3), 36, 156(3) and 200 CrPC before resort to writ jurisdiction. Janata Dal v. H.S. Chowdhary, Simranjit Singh Mann, Rajiv Ranjan Singh “Lalan” and Tehseen Poonawalla informed the Court’s caution against using PIL jurisdiction to supervise or supplant the ordinary criminal process without cogent material demonstrating institutional failure.

Ramlila Maidan Incident, Anita Thakur and D.K. Basu were treated as continuing safeguards requiring restraint, proportionality and lawful exercise of police power. However, they did not require a fresh set of rules exclusively for educational institutions. Rudul Sah, Bhim Singh and Nilabati Behera were distinguished on compensation because those cases involved established or undisputed constitutional violations requiring immediate public-law redress.

Court’s Reasoning

The Court found that the December 2019 allegations had not remained unexamined. The NHRC conducted an independent inquiry, made findings critical of aspects of police conduct and recommended remedial measures; its report remained unchallenged. Criminal cases were investigated by the Crime Branch SIT and charge-sheets were before competent courts. Jamia’s Section 156(3) application had also been adjudicated and allowed to attain finality. In that setting, no pervasive or fundamental failure of the existing mechanisms was shown so as to justify a fresh judicial commission, SIT or parallel investigation.

The Court declined to determine, in writ jurisdiction, whether force used at particular moments was necessary or excessive because that exercise required appreciation of evidence, the sequence of events, the perceived threat and conduct of persons present. Its refusal to order a fresh probe was expressly not a finding on the merits of individual allegations or culpability.

Compensation was refused because the factual basis remained disputed, the NHRC had already recommended compensation/remedial measures, the petitioners had not shown that those recommendations were pursued, individual remedies remained available, and more than six years had elapsed.

The Court likewise declined fresh campus-policing guidelines: the incident arose from a rapidly developing situation in which protests around the University had escalated into violence, and one incident could not furnish a universal procedure for every educational institution. The Court expressly clarified that this did not approve every police act or dilute the right to peaceful protest and the duty to act proportionately.

No further preservation order was considered necessary because the State had stated on affidavit that CCTV footage and relevant electronic records were preserved and formed part of the investigative material, with no concrete material showing subsequent destruction or suppression. Questions of admissibility, authenticity and evidentiary value were left to the criminal courts.

Conclusion

The Delhi High Court dismissed the entire batch of writ petitions. It found no ground to constitute an independent inquiry mechanism or SIT, transfer or reopen the investigation, direct registration of criminal cases, award compensation in writ jurisdiction, frame fresh guidelines for police action in educational institutions, or issue

additional directions for preservation of evidence. The Court nevertheless preserved the right of any individual to pursue remedies otherwise available in law, and clarified that competent authorities or courts could act on any specific offence or grievance where statutory requirements were independently satisfied. Pending applications were disposed of and there was no order as to costs.

CASE DETAILS

Case: Manoj Dhiryan v. Union of India & Ors. and connected matters

Court: High Court of Delhi at New Delhi

Case Number: W.P.(C) 13468/2019 & connected matters

Judges: Justice Vivek Chaudhary and Justice Manoj Jain

Reserved On: 24 July 2026

Date: 5 October 2026

Result: Writ petitions dismissed; pending applications disposed of; no order as to costs.

Source:
https://www.newindianexpress.com/states/odisha/2026/Oct/07/dalit-sarpanch-assault-nhrc-begins-probe

Dalit sarpanch assault: NHRC begins probe

The charges reportedly include attempt to murder, causing hurt and obstructing a public servant.

Express News Service
Updated on: 07 Oct 2026, 9:26 am

KENDRAPARA: A three-member team of the National Human Rights Commission (NHRC) on Tuesday began investigation into the alleged assault of the dalit sarpanch of Tikhiri panchayat in Mahakalapada block of the district. The team, comprising NHRC deputy SP Isam Singh, Gugan Ram and Shashi Bala Sharma, arrived in Kendrapara on Monday night for a four-day visit to conduct a detailed inquiry into a complaint filed by sarpanch Chameli Ojha (33). The team visited Mahakalapada police station on Tuesday and recorded statements of the then IIC Manas Kumar Mallick in connection with the case. The NHRC officials subsequently met Mahakalapada BDO Rabi Narayan Acharya and other staff at the block office. They also visited Ojha's house in Tikhiri and recorded her statement. Officials said the NHRC team is scheduled to meet the district collector, SP and officials of various departments. The investigators are expected to record statements of doctors at Kendrapara district headquarters hospital, officials, villagers and others connected to the case. They may also examine videos of the incident circulated on social media and accounts provided by eyewitnesses. Ojha had reportedly been assaulted and manhandled by police personnel and the BDO on June 11 after she raised allegations of corruption against officials. On June 14, a petition was filed before the NHRC alleging that Ojha had been falsely implicated in a case registered on basis of the complaint of the Mahakalapada BDO. The charges reportedly include attempt to murder, causing hurt and obstructing a public servant.

Source: https://www.heraldgoa.in/goa/nhrc-special-monitor-inspects-margao-police-station-lock-up-reviews-facilities-for-accused/491120/

NHRC Special Monitor Inspects Margao Police Station Lock-Up, Reviews Facilities for Accused
By Team Herald
Published: 7 October 2026

Margao: National Human Rights Commission (NHRC) Special Monitor Shri Mohammad Jamshed inspected the lock-up and other facilities provided for accused persons at the Margao Town Police Station.

During the inspection, Jamshed reviewed the facilities available at the police station and expressed satisfaction with the arrangements.

He said the inspection was part of a wider exercise and that he would visit several other locations to assess facilities and conditions. Jamshed also stated that he would seek a report from the Goa State Human Rights Commission as part of the review.

The inspections are aimed at assessing facilities and ensuring that the rights and basic requirements of persons in police custody are adequately addressed.

Source: https://timesofindia.indiatimes.com/city/bhubaneswar/nhrc-seeks-jeypore-activists-response-on-koraput-highway-projects/articleshow/134767433.cms

NHRC seeks Jeypore activist's response on Koraput highway projects
Lalmohan Patnaik / Oct 07, 2026, 18:55 IST

Cuttack: National Human Rights Commission (NHRC) has sought a response from a Jeypore-based human rights activist on govt's report detailing ongoing and proposed national highway projects in Koraput, Malkangiri, Nabarangpur and Rayagada districts constituting undivided Koraput district. He had alleged that poor road infrastructure was endangering the right to life of people in the region.The order was passed on Oct 6 on a complaint filed by advocate and human rights activist Anup Kumar Patro on Aug 25, 2025. Patro had alleged "systemic violation" of the Right to Life under Article 21 due to "severely inadequate" NH infrastructure and accused state and central govt authorities of inaction.The commission examined the complaint along with a report submitted by the Koraput district magistrate on May 29, 2026. The report, based on inputs from the superintending engineer, NH division, Jeypore, listed several projects being executed to improve connectivity in undivided Koraput district.After considering the material, the NHRC noted that the report "revealed about the projects which are being undertaken by NHAI to improve the road connectivity in the undivided Koraput district".The commission, however, decided to hear the complainant before proceeding further. "Before further proceeding, let a copy of the report dated 29.05.2026, be sent to the complainant for comments, if any, within four weeks," the NHRC directed.The authorities informed NHRC that construction of four-lane bypasses at Jeypore and Borigumma and a two-lane bypass with paved shoulders at Nabarangpur along NH-26 was underway. Widening of the Motu-Jeypore stretch of NH-326 to two-lane standards with paved shoulders was stated to be in progress. The detailed project report (DPR) had been submitted and the alignment finalised, the report said.The authorities further stated that upgrading the highway to a full four-lane road would be proposed to the ministry of road transport and highways (MoRTH) "as soon as traffic density and future demand warrant the expansion".Patro can now submit his comments on govt's claims regarding the ongoing works, proposed four-lane and the overall adequacy of measures being taken to address road infrastructure concerns raised in his complaint.

Source:
https://www.newindianexpress.com/states/odisha/2026/Oct/08/nhrc-seeks-activists-response-to-report-on-nh-projects-in-four-odisha-districts

NHRC seeks activist's response to report on NH projects in four Odisha districts

NHRC passed the order on October 6 on a complaint filed by human rights activist and advocate Anup Kumar Patro on August 25, 2025.

Express News Service
Updated on: 08 Oct 2026, 8:08 am

CUTTACK: The National Human Rights Commission (NHRC) has sought comments from a Jeypore-based human rights activist on a government report detailing ongoing and proposed road projects in Koraput, Malkangiri, Nabarangpur and Rayagada districts, following his complaint alleging a systemic violation of citizens' right to life due to poor national highway infrastructure in the region.

NHRC passed the order on October 6 on a complaint filed by human rights activist and advocate Anup Kumar Patro on August 25, 2025. Patro had alleged inaction by the state and central government authorities over the "severely inadequate" NH infrastructure in the four districts, which constituted undivided Koraput district.

The commission considered the complaint, taking note of a report submitted by the Koraput district magistrate on May 29. The report incorporated details furnished by the superintending engineer, NH Division, Jeypore, about road projects being undertaken to improve connectivity in the four districts.

After examining the material, the human rights body observed that the report "revealed about the projects which are being undertaken by NHAI to improve the road connectivity in the Koraput district". However, it decided to seek the complainant's response before taking further action.

"Before further proceeding, let a copy of report dated 29.05.2026, be sent to the complainant for comments, if any, within four weeks," the NHRC directed.

According to the report, construction of four-lane bypasses at Jeypore and Borigumma and a two-lane bypass with paved shoulders at Nabarangpur is underway along NH-26.

The authorities also informed the Commission that widening of the Motu-Jeypore stretch of NH-326 to two-lane with paved shoulders was in progress. The detailed project report (DPR) for the work has been submitted and the alignment finalised.

The report further stated that expansion of the highway to a full four-lane facility would be proposed before the Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) when traffic density and future demand warranted such expansion.

The order gives Patro an opportunity to place his objections or additional information before the Commission regarding the adequacy and progress of the road projects cited by the authorities.

Source: https://www.m.khaskhabar.com/news/news-police-brutality-gross-violation-of-human-rights-tikaram-jully-news-hindi-1-851216-KKN.html

खाकी की क्रूरता, मानवाधिकारों का घोर हनन : टीकाराम जूली
khaskhabar.com: बुधवार, 07 अक्टूबर 2026 7:04 PM (IST)

जयपुर। राजस्थान विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जयपुर (मुहाना थाना क्षेत्र) में पुलिस पूछताछ और हिरासत के दौरान बर्बरतापूर्ण मारपीट के चलते 19 वर्षीय युवक ऋतुराज की हुई मौत पर गहरा दुःख एवं रोष व्यक्त किया है। उन्होंने इस घटना को खाकी की क्रूरता, मानवाधिकारों का घोर हनन और कानून के राज पर बदनुमा दाग करार दिया है।

जूली ने आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, जबकि पुलिस प्रशासन ने सच्चाई को छिपाने और परिवार को डरा-धमकाकर झूठे मुकदमे दर्ज करवाने का प्रयास किया, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में अक्षम्य है। नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार की प्रशसनिक विफलता पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में हिरासत में होने वाली मौतों और पुलिस ज्यादती के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। सरकार का पुलिस प्रशासन पर कोई अंकुश नहीं रह गया है।

उन्होंने कहा कि घटना में संलिप्त सभी सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों व कर्मियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से बीएनएस की धारा-103 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जाना चाहिए। जूली ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश की निगरानी में न्यायिक जांच करवाये जाए एवं थाने के सीसीटीवी फुटेज और मेडिकल रिपोर्ट को बिना किसी छेड़छाड़ के न्यायिक रिकार्ड में दर्ज किया जाए। साथ ही पीड़ित परिवार को तुरन्त आर्थिक सहायता और परिवार के एक आश्रित को सरकारी नौकरी दिये जाने की मांग की है।

Source: https://www.livehindustan.com/national/story-bonded-labor-complaint-filed-with-national-human-rights-commission-in-bhagalpur-201791373613358.html

भागलपुर। आयोग में बंधुआ मजदूरी की शिकायत पर जांच दल में इंस्पेक्टर शामिल
Oct 07, 2026 05:16 pm IST
By Hindustan | Bureau हिन्दुस्तान , भागलपुर

भागलपुर के मजदूर सदानंद यादव ने बंधुआ मजदूरी को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत की। आयोग ने जांच का निर्देश दिया है। उप-श्रमायुक्त के कार्यालय ने पुलिस अधिकारी को जांच दल में शामिल करने का आदेश दिया है। जांच प्रक्रिया मानक संचालन प्रक्रिया के तहत चलायी जाएगी। भागलपुर। शहर में स्थित अन्नपूर्णा और आजा ट्रांसपोर्ट के अधीन कार्य करने वाले मजदूर सदानंद यादव ने बंधुआ मजदूरी को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत की है। वहां वाद दायर करने के बाद जांच का निर्देश दिया गया है। भागलपुर समाहरणालय के अंतर्गत उप-श्रमायुक्त के कार्यालय ने जांच दल में पुलिस अधिकारी को शामिल करने का आदेश दिया है। उसी आदेश के आलोक में एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने मोजाहिदपुर सर्किल इंस्पेक्टर गोपाल कुमार सिंह को जांच दल के लिए नामित किया है। बंधुआ मजदूरी को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया के तहत जांच का निर्देश दिया गया है।

Source: https://www.jagran.com/madhya-pradesh/indore-mandsaur-teen-dies-after-alleged-police-custody-beating-in-jaipur-40397778.html

जयपुर पुलिस की कस्टडी में पिटाई से मंदसौर के किशोर की मौत, 11 दिन ICU में रहा; मजिस्ट्रियल जांच शुरू
By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
Published: Wed, 07 Oct 2026 11:10 PM (GMT+05:30)

मंदसौर के 16 वर्षीय ऋतुराज लोहार की जयपुर में 11 दिन आईसीयू में इलाज के बाद मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस हिरासत में मारपीट का आरोप लगाया है। मामले में न्यायिक जांच शुरू हो गई है और मजिस्ट्रेट ने परिजनों के बयान दर्ज करने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया।

HighLights

22 लाख रुपये के सस्ते सोने के विवाद में पिता-पुत्र से हुई थी पूछताछ।

परिजनों ने पुलिस हिरासत में मारपीट का गंभीर आरोप लगाया।

मामले की मजिस्ट्रियल जांच, पांच डॉक्टरों के पैनल ने किया पीएम।

डिजिटल डेस्क, मंदसौर। मंदसौर जिले के मनासा खुर्द निवासी 16 वर्षीय ऋतुराज लोहार की जयपुर के अस्पताल में 11 दिन आईसीयू में उपचार के बाद मौत हो गई। स्वजन ने जयपुर के मुहाना थाने में पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट किए जाने का आरोप लगाया है। मौत के बाद स्वजन ने पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया था। इसके बाद मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हुए। मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट सौरभ बंसल ने स्वजन के बयान दर्ज किए। इसके बाद स्वजन की सहमति से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत पांच चिकित्सकों के पैनल ने शव का पोस्टमार्टम किया।

मृतक की मां हेमाबाई ने बताया कि उनके पति प्रकाश लोहार दुबई में वेल्डिंग का काम करते हैं। 17 सितंबर को वह जयपुर पहुंचे और होटल रियांश में ठहरे थे। इसके बाद उनका मोबाइल बंद हो गया। अगले दिन 18 सितंबर को एक व्यक्ति ने उनके 16 वर्षीय बेटे ऋतुराज को फोन कर जयपुर बुलाया। जयपुर पहुंचने के कुछ समय बाद ऋतुराज ने फोन कर बताया कि उसे और पिता को चार-पांच लोगों ने पकड़ रखा है। 22 सितंबर को प्रकाश के दोस्त ललित ने स्वजन को फोन कर बताया कि ऋतुराज गंभीर हालत में जयपुर के नारायण अस्पताल में भर्ती है। स्वजन जयपुर पहुंचे तो ऋतुराज आईसीयू में बेहोश था।

स्वजन का आरोप है कि थाने में पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट की, जिससे सिर में गंभीर चोट आई और वह बेहोश हो गया। इसके बाद उसे होश नहीं आया। 11 दिन उपचार के बाद पांच अक्टूबर को उसकी मौत हो गई। स्वजन के अनुसार जयपुर के कुछ लोगों ने प्रकाश लोहार को दुबई से सस्ता सोना लाने के लिए चार लाख रुपये दिए थे। राशि प्रकाश के खाते में नहीं पहुंचने के कारण वह सोना नहीं ला पाया। बाद में जयपुर पहुंचने पर कुछ लोगों ने उसे पुलिसकर्मियों की मदद से पकड़ लिया। स्वजन का दावा है कि प्रकाश के पास दो लाख रुपये थे और उसने बेटे ऋतुराज को बुलाया था। इसके बाद ऋतुराज को पुलिस की हिरासत में रखकर मारपीट की गई।

वहीं मुहाना थाना प्रभारी मुकेश खराड़िया ने बताया कि प्रकाश लोहार के खिलाफ दुबई से सस्ता सोना लाने के नाम पर करीब 22 लाख रुपये लेने की शिकायत मिली थी। पुलिस इसी मामले में कार्रवाई कर रही थी। उनके अनुसार नाबालिग को उसके स्वजन ही थाने लेकर आए थे और थाने आने के बाद उसकी तबीयत खराब हुई। पुलिस ने उसके साथ मारपीट नहीं की। मामले की जांच चल रही है।

Source: https://www.livehindustan.com/national/story-human-rights-commission-investigates-young-woman-s-death-after-alleged-rape-and-betrayal-201791402654283.html

युवती की मौत के मामले में मानवाधिकार आयोग की टीम पहुंची अमरिया
Oct 08, 2026 01:22 am IST
ByHindustan | Bureau हिन्दुस्तान, पीलीभीत

अमरिया में एक युवती की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जांच शुरू की। युवती ने प्रेमी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। धोखा मिलने के बाद उसने विषाक्त पदार्थ खा लिया। आयोग की टीम ने घटना से जुड़े लोगों के बयान दर्ज किए और जानकारी इकट्ठा की।

अमरिया। प्रेमी के धोखा देने और पुलिस की ओर से दर्ज मुकदमे में अंतिम रिपोर्ट लगाए जाने के बाद विषाक्त पदार्थ खाने से हुई युवती की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जांच शुरू कर दी है। आयोग की टीम मंगलवार को अमरिया पहुंची और घटना से जुड़े लोगों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए। टीम ने युवती की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे, पुलिस की विवेचना और उसमें लगाई गई अंतिम रिपोर्ट से संबंधित जानकारी भी जुटाई। जांच की प्रक्रिया को टीम ने गोपनीय रखा।

अमरिया कस्बे की निवासी युवती ने 18 मई 2024 को थाने में कस्बे के ही एक युवक के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी ब्रजवीर सिंह ने की थी। पुलिस ने आठ जून 2024 को विवेचना पूरी करने के बाद मामले में अंतिम रिपोर्ट (एफआर) लगाकर उसे न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया था। इसी बीच 20 अक्तूबर 2024 को आरोपी युवक ने दूसरी जगह शादी कर ली। इसकी जानकारी युवती को हुई तो उसने मामले में कार्रवाई के लिए प्रयास शुरू किए। इसी दौरान सात नवंबर 2024 को युवती ने विषाक्त पदार्थ खा लिया। इसके बाद वह अमरिया थाने पहुंची, जहां से पुलिस ने उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। युवती की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे बरेली रेफर कर दिया। बरेली में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

घटना के बाद मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंचा। आयोग ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जांच के लिए टीम भेजी। मंगलवार को अमरिया पहुंची टीम ने घटना से जुड़े लोगों से जानकारी लेकर उनके बयान दर्ज किए। टीम ने युवती की ओर से दर्ज मुकदमे और पुलिस की विवेचना से संबंधित तथ्यों को भी समझा। इसके बाद टीम माधोटांडा क्षेत्र में पहुंची और वहां भी कुछ लोगों के बयान दर्ज किए। आयोग की टीम ने जांच के दौरान जुटाई गई जानकारी और अपनी आगे की कार्रवाई को गोपनीय रखा। एसपी सुकीर्ति माधव ने बताया कि टीम जांच करने आई थी। टीम के सहयोग के लिए सहायक पुलिस अधीक्षक नताशा गोयल को लगाया गया था।

Source: https://www.themooknayak.com/tribal-news/ken-betwa-displacement-struggle-chita-andolan-completes-25-days-200-citizens-write-to-nhrc-centre-and-mp-government

मझगवां-रुंझ बांध प्रभावितों के हक में 200 से ज़्यादा नागरिक संगठनों की आवाज़, पुलिस हिंसा और गिरफ्तारियों की निंदा

आदिवासी हक़, न्यायपूर्ण पुनर्वास और कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग

The Mooknayak Published on: 07 Oct 2026, 10:13 am

केन-बेतवा परियोजना से प्रभावित समुदायों के 'चिता आंदोलन' के 25 दिन पूरे होने पर, भारत भर से 200 से ज़्यादा चिंतित नागरिकों व जन-संगठनों ने NHRC, NCST, केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को पत्र लिखा। उन्होंने आदिवासी समुदायों पर पुलिस हिंसा के खिलाफ़ कार्रवाई और मझगवां व रुंझ बांध से प्रभावित लोगों के उचित और न्यायपूर्ण पुनर्वास की मांग की।

यह संघर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मझगवां बांध से प्रभावित कुछ इलाकों में जल-स्तर बढ़ रहा है, जिससे आदिवासी ग्रामीणों के घर और खेत डूब रहे हैं। हस्ताक्षरकर्ताओं ने नाराज़गी जताई कि विरोध कर रहे समुदायों की जायज़ शिकायतों को संवाद से सुलझाने के बजाय, प्रशासन ने सितंबर के आखिरी हफ्ते में आदिवासी महिलाओं और पुरुषों पर पुलिस हिंसा की और 'जय किसान संगठन' के अमित भटनागर, दिव्या अहिरवार और हिसाबी राजपूत समेत कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया।

हस्ताक्षरकर्ताओं ने लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की जो बिना दबे अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं, और अमित भटनागर को लेकर चिंता जताई, जिनकी राज्य-हिरासत में भूख हड़ताल के 8 दिन पूरे हो गए हैं। उन्होंने अधिकारियों से केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से प्रभावित सभी छोटे किसानों और आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने का आह्वान किया ताकि उनकी आवाज़ और भविष्य डूब न जाएं।

यह पत्र राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों के साथ-साथ, केंद्रीय जनजातीय और जल संसाधन मंत्रियों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और MP के जल संसाधन मंत्री को भेजा गया, जिनमें कानूनी और संवैधानिक अधिकारों के पालन की मांग की गई।

हस्ताक्षर करने वालों में जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद, वकील, पर्यावरणविद, शोधकर्ता शामिल हैं, जैसे: प्रो. रूप रेखा वर्मा, प्रो. भंग्या भुक्या, मेधा पाटकर, प्रफुल्ल सामंतरा, आशीष कोठारी, सौम्या दत्ता, जॉन दयाल, शबनम हाशमी, सुधीर वोम्बटकेरे, डॉ. के. बाबू राव, डॉ. गैब्रिएल डिट्रिच, डॉ. आदित्य निगम, सेड्रिक प्रकाश, दीपक ढोलकिया, नीलम अहलूवालिया, राजकुमार सिन्हा, अफलातून, राजेश रामकृष्णन, चित्तरूपा पालित, कैलाश मीणा, छाया दातार, अम्मू अब्राहम, श्रीपाद धर्माधिकारी, अरुंधति धुरू, डॉ. नवशरण सिंह, डॉ. सागरी रामदास, डॉ. सुहास कोल्हेकर, सिंथिया स्टीफन, सुजाता गोथोस्कर, अभिजीत प्रभुदेसाई, कल्याणी मेनन सेन, हसीना खान, चयनिका शाह, थॉमस फ्रेंको, अनमोल ओहरी, एडवोकेट मिनी मैथ्यू, एडवोकेट निकिता सोनावाने, एडवोकेट प्योली स्वातिजा, एडवोकेट शालिनी गेरा, मानशी अशर, एसपी रवि, निशा बिस्वास, सुजाता मधोक, प्रीति संपत, ईश्वर, प्रियदर्शिनी, मीरा संघमित्रा और कई संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य लोग।

हस्ताक्षर करने वालों की मुख्य मांगें:

जेल में बंद सभी कार्यकर्ताओं को तुरंत रिहा किया जाए और आंदोलन पर किसी प्रकार की दमन न हो।

सभी प्रभावित परिवारों और विस्थापितों का ज़मीन और आजीविका के आधार पर पूरा पुनर्वास किया जाए; उन्हें नागरिक सुविधाओं वाले घर और मुआवज़ा दिया जाए। यह सब निष्पक्ष सर्वे के आधार पर हो और किसी भी योग्य विस्थापित को इससे बाहर न रखा जाए।

भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास अधिनियम, 2013; वन अधिकार अधिनियम, 2006 और जैव विविधता अधिनियम, 2002 के सभी प्रावधानों को सही रूप से लागू करना।

शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे आदिवासियों पर पुलिस की कार्रवाई और पुनर्वास प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की स्वतंत्र जांच; साथ ही, कानून के अनुसार (जिसमें SC & ST (PoA) अधिनियम, 1989 के प्रावधान भी शामिल हैं) सभी उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई।

केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के सामाजिक, पर्यावरणीय और जल-संबंधी (हाइड्रोलॉजिकल) प्रभावों (लागत और लाभ) की व्यापक समीक्षा।

संयुक्त रूप से जारीकर्ता: जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय (NAPM), राष्ट्रीय जल वायु और पर्यावर्णीय न्याय मंच (NACEJ), राष्ट्रीय नदी घाटी मंच और दिल्ली सॉलिडैरिटी ग्रुप (DSG)

Source: https://www.inextlive.com/top-scholarships-and-internships-to-apply-for-in-october-2026-1791380527

अक्टूबर 2026 में अप्लाई करें ये स्कॉलरशिप और इंटर्नशिप, स्टूडेंट्स को मिलेगा फाइनेंशियल सपोर्ट और एक्सपीरियंस
By: Vishal Yadav | Updated Date: Wed, 07 Oct 2026 19:13:47 (IST)

अक्टूबर 2026 में स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप और इंटर्नशिप के कई शानदार मौके हैं। विद्या धन और SDEF स्कॉलरशिप के साथ NHAI और NHRC की विंटर इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। जानिए एलिजिबिलिटी, लास्ट डेट, फाइनेंशियल सपोर्ट, स्टाइपेंड और अप्लाई करने का तरीका।

अक्टूबर 2026 स्टूडेंट्स के करियर को एक नई डायरेक्शन देने के लिए कई बेहतरीन मौके लेकर आया है। अगर आप अपनी पढ़ाई के लिए फाइनेंसियल सपोर्ट या फिर जॉब मार्केट के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सर्च कर रहे हैं तो इस महीने कई टॉप स्कॉलरशिप्स और इंटर्नशिप्स के फॉर्म भरे जा रहे हैं। ये मौके आपके पैसों की टेंशन को कम करेंगे और आपके रिज्यूमे को भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे।

विद्या धन स्कॉलरशिप
विद्या धन स्कॉलरशिप उन ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो पैसों की प्रॉब्लम की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। ये स्कीम स्पेशली 11वीं और 12वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के लिए डिजाइन की गई है। इसमें सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स को उनकी आगे की स्टडीज के लिए हर साल 10 हजार रुपए से लेकर 75 हजार रुपए तक की फाइनेंसियल हेल्प दी जाती है।
लास्ट डेट: 25 अक्टूबर 2026
अप्लाई लिंक: https://www.vidyadhan.org

2। SDEF स्कॉलरशिप (Swami Dayanand Education Foundation)
अगर आपने हाल ही में कॉलेज में एडमिशन लिया है तो SDEF आपको बढ़िया फाइनेंसियल असिस्टेंस दे रहा है। ये स्कॉलरशिप मेनली प्रोफेशनल और ओपन डिग्री कोर्स के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। इसके तहत एलिजिबल स्टूडेंट्स को कॉलेज फीस और दूसरे खर्चों के लिए हर साल 50 हजार रुपए तक का अमाउंट दिया जाता है। इससे आपके कॉलेज की पढ़ाई की टेंशन काफी हद तक खत्म हो जाएगी।
लास्ट डेट: 31 अक्टूबर 2026
अप्लाई लिंक: https://www.swamidayanand.org

3। NHAI विंटर इंटर्नशिप (National Highways Authority of India)
अगर आपका इंटरेस्ट रोड कंस्ट्रक्शन, हाईवे डेवलपमेंट और सिविल फील्ड में है तो NHAI आपके लिए एक शानदार विंटर इंटर्नशिप लाया है। ये चांस फुल-टाइम अंडरग्रेजुएट (UG) और पोस्टग्रेजुएट (PG) स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने कोर्स के प्री-फाइनल या फाइनल ईयर में हैं। इस बड़े गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करने के रियल एक्सपीरियंस के साथ आपको 20 हजार रुपए प्रति महीने का स्टाइपेंड भी मिलेगा।
लास्ट डेट: 20 अक्टूबर 2026
अप्लाई लिंक: https://nhai.gov.in

NHRC विंटर इंटर्नशिप (National Human Rights Commission)
लॉ और ह्यूमन राइट्स के फील्ड में अपना करियर बनाने वाले स्टूडेंट्स के लिए NHRC की विंटर इंटर्नशिप एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। LLB, LLM और ह्यूमन राइट्स से जुड़े कोर्सेस कर रहे स्टूडेंट्स इसमें बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को 12 हजार रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा और साथ ही सफर के लिए 3rd AC ट्रेन का फेयर भी दिया जाएगा। ये एक्सपीरियंस आपके करियर के लिए गेम-चेंजर साबित होगा।
लास्ट डेट: 15 अक्टूबर 2026
अप्लाई लिंक: https://nhrc.nic.in

Dainik Bhaskar, Online News, 08/10/2026

Source: https://www.bhaskar.com/g/local/bihar/patna/news/nhrcs-grand-hearing-at-gyan-bhawan-dbp-139284535.html

ज्ञान भवन में एनएचआरसी की महासुनवाई: सेप्टिक टैंक में मौतों पर 30-30 लाख मुआवजा, 25 केस बंद

पटना3 घंटे पहले -

कॉपी लिंक 30 में से 25 मामलों का मौके पर निपटारा

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की ज्ञान भवन में हुई सुनवाई के पहले दिन ऐतिहासिक फैसले आए। आयोग अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यम, सदस्य न्यायमूर्ति डॉ. विद्युत रंजन सारंगी व विजया भारती सयानी की पीठ ने सीतामढ़ी में 2022 में सेप्टिक टैंक सफाई में मृत दो मजदूरों के परिजनों को 30-30 लाख (कुल 60 लाख) मुआवजा देने का आदेश दिया। इसकी शिकायत आमिर सुबहानी ने की थी। आयोग ने सरकार को कुल करीब 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया। 5 घंटे चली सुनवाई में 17 जिलों के 30 मामले आए, जिनमें 25 केस ऑन-द-स्पॉट बंद कर दिए गए। गुरुवार को 40 केस सुने जाएंगे। एडीजी मुख्यालय केएस अनुपम, गृह विशेष सचिव छत्रनील सिंह, जेल आईजी रजनीश कुमार सिंह व डीआईजी लीगल सुशील कुमार मौजूद थे। 30 मामलों में सर्वाधिक 6 जेल हिरासत में मौत, 6 महिला प्रताड़ना, 2 बाल सुधार गृह में मौत व 11 स्वतः संज्ञान के केस थे। जिलों में पटना के 8, मुजफ्फरपुर के 5, पूर्वी चंपारण-दरभंगा के 2-2 मामले थे।

मामले और निर्देश:

ज्ञान भवन में ऑन-द-स्पॉट फैसले

सेप्टिक टैंक में मौत (सीतामढ़ी, 2022) – आमिर सुबहानी की शिकायत।
निर्देश: दोनों मृतकों के आश्रितों को 30-30 लाख रु. मुआवजे का आदेश।

रेप-चिटफंड पीड़िता को धमकी (मुजफ्फरपुर) – अहियापुर थाने के केस में धमकी की शिकायत।
निर्देश: एडीजी केएस अनुपम को 2 हफ्ते में महिला आईपीएस के नेतृत्व में एसआईटी बनाने व नंबर देने का आदेश।

बेऊर जेल में मौत (पटना) – राजवीर सिंह (55 वर्ष) व सचिन कुमार (23 वर्ष, तिसखोर) की मौत का मामला।
निर्देश: राजवीर के परिजनों को 5 लाख व सचिन को 3 लाख मुआवजा और इलाज के निर्देश।

11 साल की बच्ची से गैंगरेप-हत्या (मनेर): आरोपी भोला राय मामले में अनाथ बच्ची की फुआ, दादी व भाई पहुंचे।
निर्देश: फुआ के खाते में 5 लाख एफडी कराने व मुजफ्फरपुर की दिव्यांग महिला की शिकायत पर संज्ञान।

मिड-डे मील में लापरवाही (नालंदा, पटना, मोकामा): बच्चे बीमार पड़ने व मेकरा में सांप की अफवाह।
निर्देश: मेकरा केस बंद कर स्वच्छता व भोजन जांच के निर्देश।

तंत्र की नाकामी पर आयोग का चाबुक

प्रशासनिक लापरवाही: सेप्टिक टैंक में मौतें व मिड-डे मील में बच्चे बीमार पड़ना जिला प्रशासन की घोर लापरवाही है।

जेल प्रबंधन की विफलता: इलाज के अभाव में हिरासत में मौत जेल प्रशासन की नाकामी है, जहां अफसरों पर कार्रवाई जरूरी है।

त्वरित न्याय का संदेश: एक दिन में 25 केस निपटाकर आयोग ने साफ किया कि मानवाधिकार हनन बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसा होने पर कार्रवाई भी की

जाएगी।